E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
https://multiresearchjournal.theviews.in

Received: 13-04-2024
Accepted: 29-06-2024

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 2; Issue 3; 2024; Page No. 497-501

सांस्कृतिक प्रथाओं, नीतियों और धार्मिक मूल्यों के गोंड जनजाति की महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव की जाँच करना

[1]Anita Nagle, [2]Dr. Santosh Salve and [3]Dr. Archana Tripathi

[1]Research Scholar, Department of Sociology, Madhyanchal Professional University, Bhopal, Madhya Pradesh, India
[2, 3]Department of Sociology, Madhyanchal Professional University, Bhopal, Madhya Pradesh, India

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15174008

Corresponding Author: Anita Nagle

सारांश

भारत में आदिवासी महिलाएँ आदिवासी पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनती हैं और वे अपने परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं लेकिन उनकी आय के स्रोत सीमित हैं। कम आय के कारण अधिक हाथ श्रम की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप वे अपने बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भेजने से हिचकते हैं। अध्ययन का उद्देश्य समग्र सूचकांक के अंतर्गत आने वाले तथ्यों को उजागर करना है; मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति। अध्ययन ने इस तथ्य को उजागर किया कि क्या आदिवासी लोग इन क्षेत्रों में चल रहे शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूक और लाभान्वित हैं या नहीं। शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक डेटा अप्रैल माह 2021 के दूसरे सप्ताह के दौरान एकत्र किया गया है।

मूल शब्दः महिलाएँ, सामाजिक, आर्थिक, स्थिति, और विश्लेषण।

प्रस्तावना

भारत में रहने वाली लगभग 10.45 करोड़ स्वदेशी आबादी आर्थिक असमानता और सामाजिक कलंक के कारण दांव पर लगी है। कोविड के बाद हमारी दुनिया गर्म हो गई, असंख्य मौतें, आर्थिक अवसाद, बेरोजगारी, संगरोध, अपरिहार्य लॉकडाउन, यात्रा पर प्रतिबंध, ये स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक चीजें थीं। उस समय खानाबदोश महिलाएं जो पशुपालन जैसे कामों में लगी हुई थीं, वे सबसे ज्यादा पीड़ित थीं। उस समय लकड़ी का संग्रह भी प्रतिबंधित था। उस समय शारीरिक दूरी, खरीदारों की कमी और आवाजाही के प्रतिबंधों के कारण डेयरी उत्पादों की मांग में कमी आई थी। आदिवासी महिलाएँ वन औषधि, पेड़ का गोंद, फल, शहद, आंवला जैसे लघु वन उत्पादों पर भी निर्भर हैं।

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि महिलाएँ सभी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों। इस भागीदारी के बिना कोई राष्ट्र सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे समाज में महिलाओं का बहुत महत्व है। पिछले कुछ दशकों में समाज में महिलाओं की भूमिका को काफ़ी अनदेखा किया गया है, लेकिन अब लोगों के लिए यह एक अलग नज़रिया बन गया है। शुरुआती दिनों में महिलाओं को पत्नियों के रूप में देखा जाता था, जिनका काम खाना बनाना, सफ़ाई करना और बच्चों की देखभाल करना होता था। उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी, जबकि पुरुष नौकरी करते थे और बिल चुकाते थे।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मूल रूप से शिक्षा, आय और अवसर जैसे विभिन्न पहलुओं के संयोजन के रूप में मापा जाता है। यह किसी व्यक्ति के कार्य अनुभव और किसी व्यक्ति या परिवार के दूसरों के साथ सामाजिक और आर्थिक संबंधों का एक आर्थिक और समाजशास्त्रीय संयुक्त कुल माप है। यह कहा जा सकता है कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति की जांच से पता चलता है कि संसाधनों, शक्ति, नियंत्रण और विशेषाधिकार से संबंधित मुद्दों की प्राप्ति में असमानता है।

महिलाएँ किसी भी संभव तरीके से अपनी राय व्यक्त करेंगी ताकि वे अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें और उन्होंने ऐसा किया भी। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं ने अपनी जीवनशैली में काफ़ी सुधार किया है, चाहे वे सरकारी पद पर हों या नौकरी करना और खुद का भरण-पोषण करना। पुरुषों में इस बात की प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका बच्चा हो चुका है और पिता पर्याप्त रूप से प्रतिबद्ध नहीं है या "पिता" बनने

के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि महिलाओं की स्थिति दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है।

साहित्य समीक्षा

अबू तैयब एमएम (2017) [1] ने अपने अध्ययन "भारत में जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति" में विश्लेषण किया कि केंद्र और राज्य सरकारों और योजनाकारों ने अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उत्थान के उद्देश्य से कई नीतियां विकसित और लागू भी की हैं; जो ऐतिहासिक कारणों से ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस प्रकार, मौजूदा अध्ययन भारत में जनजातीय समुदायों की कई सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करता है। इसलिए, अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि जनजातीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

आशीष महापात्रा (2017) [2] द्वारा "समकालीन ओडिशा के आदिवासी समुदायों में महिलाओं का आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण" पर एक अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ओडिशा की आदिवासी महिलाएँ अपने-अपने समुदायों में सम्मानजनक स्थिति का आनंद ले रही हैं, वे सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस पत्र की मुख्य परिकल्पना यह दर्शाती है कि ओडिशा में आदिवासी महिलाओं के समुदायों की स्थिति आर्थिक और राजनीतिक रूप से अर्जित है, गैर-आदिवासी महिलाओं की तुलना में जो अधिक सशक्त हैं। इस प्रकार, ओडिशा के आदिवासी समुदायों में सशक्त महिलाओं की स्थिति को मध्यम रूप से उच्च कहा जा सकता है

मंजूनाथ और गंगाधर (2017) [3] ने अपने अध्ययन "जेनुकुरुबा आदिवासी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति: चामराजनगर जिले, कर्नाटक का एक केस स्टडी" में विश्लेषण किया कि इस पत्र का उद्देश्य जेनुकुरुबा आदिवासी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाना और उसी के समग्र विकास के लिए तरीके और साधन सुझाना है। जुनुकुरुबा समुदाय के पास समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत, शाश्वत परंपराएं हैं, लेकिन सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण की कमी है। वे धन नहीं बना सकते थे; वे जमीन और संपत्ति आदि नहीं रख सकते थे। किसी भी तरह, सरकारों ने आरक्षण के रूप में संवैधानिक राहत की पेशकश की।

मनोज एम. गामित और पंकज एस. सुवेरा (2017) [4] द्वारा आयोजित "आदिवासी और गैर-आदिवासी कॉलेज के छात्रों के बीच सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन" पर एक अध्ययन ने मूल्यांकन किया कि शोध का उद्देश्य आदिवासी और गैर-आदिवासी कॉलेज के छात्रों के बीच सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है और अन्वेषक ने आदिवासी और गैर-आदिवासी कॉलेज के छात्रों का चयन किया। दोनों समूहों में 240 छात्र हैं। प्रत्येक समूह में 120 आदिवासी क्षेत्र और दूसरे समूह में 120 गैर-आदिवासी क्षेत्र के कॉलेज के छात्र हैं। तापी जिले से डेटा एकत्र किया गया था। डेटा संग्रह के लिए सिंह, श्याम और कुमार (2006) द्वारा विकसित व्यक्तिगत डेटाशीट और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पैमाने का उपयोग किया गया था।

संपा दास (2017) [5] ने अपने अध्ययन "बीरभूम के पाथरघाटा गांव में शिक्षा के माध्यम से संथाल महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण" में पाया कि महिलाओं को सशक्त बनाना हमेशा से दुनिया भर में प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं में मानसिक और शारीरिक क्षमता, शक्ति और कौशल का विकास है ताकि वे सामाजिक परिवेश में सार्थक रूप से काम कर सकें; जिससे उन्हें सामाजिक मान्यता का अधिक अनुकूल स्तर प्राप्त हो और परिणामस्वरूप उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो। शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है।

शोध पद्धति

संरचित प्रश्नावली शोधकर्ता द्वारा स्वयं तैयार की गई है। इसमें 28 प्रश्न और प्रासंगिक पृष्ठभूमि जानकारी शामिल है। विश्लेषण के समय इन प्रश्नों को 7 कारकों में समेट दिया गया है। सभी प्रश्न उन चरों से संबंधित हैं जो महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। ये चर हैं जैसे कि उनकी निर्णय लेने की शक्ति, बैंकों, समाज, राजनीति और दुनिया के बारे में उनकी जागरूकता, उनके परिवार में उनका महत्व, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सुरक्षा, स्वतंत्रता, उनकी उत्पादकता आदि। पृष्ठभूमि की जानकारी में उनका नाम, आयु, विवाह की आयु, जाति, उनका परिवार प्रकार, शिक्षा और उनके बच्चों की संख्या आदि शामिल हैं। प्रश्नावली में एक सुझाव बॉक्स भी है जिसमें उत्तरदाताओं से उनके घर पर हमारी उपस्थिति के बारे में कुछ सुझाव लिए गए हैं।

डेटा विश्लेषण

मध्य प्रदेश में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है जो पहले उद्देश्य को पूरा करता है। जमीनी स्तर पर महिलाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए प्रश्नावली में विभिन्न प्रकार के संकेतक शामिल हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से उनकी स्थितियों पर प्रभाव डालते हैं, ये संकेतक उनकी निर्णय लेने की शक्ति, जागरूकता, उनकी उत्पादकता, उनके मूल्य और परिवार में उनकी स्वतंत्रता, उनकी सुरक्षा और संरक्षा आदि को परिभाषित करते हैं। प्रश्नावली में 28 प्रश्न शामिल हैं जो उपरोक्त संकेतकों का हिस्सा हैं। उत्तरदाताओं से कुछ पृष्ठभूमि की जानकारी भी एकत्र की गई है जो सीधे उनकी स्थिति पर भी प्रभाव डालती है, ये उनकी वर्तमान आयु, विवाह की आयु, योग्यता, उनके बच्चे, परिवार का मुखिया, राशन कार्ड का प्रकार और उनके परिवार का प्रकार आदि हैं। इस जानकारी ने विश्वसनीय और उचित परिणाम प्राप्त करने में बहुत मदद की।

आर्थिक स्थिति

तालिका 1: उत्तरदाताओं का मासिक आय स्तर

मासिक आय	शिक्षित आदिवासी महिला	अशिक्षित आदिवासी महिला	कुल
1000 से नीचे	101 (35.2)	61 (31.1)	162 (33.5)
1001 - 3000	71 (24.7)	48 (24.5)	119 (24.6)
3001 - 5000	43 (15.0)	14 (7.1)	57 (11.8)
5000 से ऊपर	72 (25.1)	73 (37.2)	145 (30.0)
कुल	287 (100.0)	196 (100.0)	483 (100.0)

स्रोत: नमूना डेटा के आधार पर अन्वेषक की गणना

शिक्षित आदिवासी महिला और अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र उत्तरदाताओं का मासिक आय स्तर तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है। यह पाया गया कि कुल मिलाकर, शिक्षित आदिवासी महिला उत्तरदाताओं में, महिला उत्तरदाताओं का एक प्रमुख समूह 35.2 प्रतिशत है, जिनकी मासिक आय 1000 से कम है, और केवल 15.0 प्रतिशत ही 3001 से 5000 रुपये प्रति माह कमाती

हैं। अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र उत्तरदाताओं में, 37.2 प्रतिशत महिलाओं की मासिक आय 5000 रुपये से अधिक है, और केवल 7.1 प्रतिशत ही 3001 से 5000 रुपये के बीच कमाती हैं। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिक्षित आदिवासी महिला और अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र उत्तरदाताओं का बहुमत यानी 35.2 प्रतिशत मासिक आय 1000 से कम है, और कुछ उत्तरदाताओं की मासिक आय 3001-5000 के बीच है।

तालिका 2: भुगतान प्रक्रिया

भुगतान प्रक्रिया	शिक्षित आदिवासी महिला	अशिक्षित आदिवासी महिला	कुल
दैनिक	84 (29.3)	91 (46.4)	175 (36.2)
साप्ताहिक	124 (43.2)	80 (40.8)	204 (42.2)
महीने के	79 (27.5)	25 (12.8)	104 (21.5)
कुल	287 (100.0)	196 (100.0)	483 (100.0)

स्रोत: नमूना डेटा के आधार पर अन्वेषक की गणना

शिक्षित आदिवासी महिला और अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र के उत्तरदाताओं की भुगतान प्रक्रिया ऊपर दी गई तालिका 2 में दी गई है। कुल शिक्षित आदिवासी महिला उत्तरदाताओं में से बहुसंख्यक समूह शिक्षित आदिवासी महिला उत्तरदाताओं का 43.2 प्रतिशत साप्ताहिक भुगतान करता है, 29.3 प्रतिशत दैनिक भुगतान का पालन करते हैं, और शेष उत्तरदाता मासिक प्रक्रिया चुनते हैं। कुल अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र के उत्तरदाताओं के संबंध में उत्तरदाताओं का एक प्रमुख समूह 46.4 प्रतिशत दैनिक भुगतान मोड चुनता है, 40.8 प्रतिशत साप्ताहिक भुगतान मोड पसंद करते हैं, और केवल 12.8 प्रतिशत मासिक भुगतान मोड का उपयोग करते हैं। इसलिए, यह इंगित करता है कि शिक्षित आदिवासी महिला और अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र के लगभग आधे उत्तरदाता साप्ताहिक भुगतान मोड चुनते हैं, जिनमें से अधिकतर 46.4 प्रतिशत शिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र के लोग हैं।

तालिका 3: भुगतान का तरीका

भुगतान का तरीका	शिक्षित आदिवासी महिला	अशिक्षित आदिवासी महिला	कुल
दयालु	109 (38.0)	40 (20.4)	149 (30.8)
नकद	175 (61.0)	153 (78.1)	328 (67.9)
कोई और	3 (1.0)	3 (1.5)	6 (1.2)
कुल	287 (100.0)	196 (100.0)	483 (100.0)

स्रोत: नमूना डेटा के आधार पर अन्वेषक की गणना

तालिका 3 शिक्षित आदिवासी महिला और अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र के उत्तरदाताओं द्वारा किए गए भुगतान के एक अलग प्रकार को इंगित करती है। तालिका के अनुसार, आधे से अधिक शिक्षित आदिवासी महिला उत्तरदाताओं (61.0 प्रतिशत) भुगतान के लिए नकद का उपयोग करती हैं और 1.0 प्रतिशत कुछ अन्य मोड चुनते हैं। कुल अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र के उत्तरदाताओं में से 78.1 प्रतिशत उत्तरदाता नकद भुगतान मोड का उपयोग कर रहे हैं, और 1.5 प्रतिशत कुछ अन्य मोड चुन रहे हैं। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षित आदिवासी महिला और अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र के उत्तरदाताओं में से 61.0 प्रतिशत और 78.1 प्रतिशत से अधिक ने लेनदेन के लिए नकद भुगतान का विकल्प चुना है और कुछ उत्तरदाताओं ने अन्य भुगतान मोड को चुना है।

तालिका 4: पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलने के बारे में उत्तरदाताओं की राय

प्रतिक्रिया	शिक्षित आदिवासी महिला	अशिक्षित आदिवासी महिला	कुल
हाँ	180 (62.7)	128 (65.3)	308 (63.8)
नहीं	107 (37.3)	68 (34.7)	175 (36.2)
कुल	287 (100.0)	196 (100.0)	483 (100.0)

स्रोत: नमूना डेटा के आधार पर अन्वेषक की गणना

शिक्षित आदिवासी महिला और अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र के उत्तरदाताओं की पुरुषों की तुलना में महिलाओं को मिलने वाले कम वेतन के बारे में राय ऊपर दी गई तालिका 4. में प्रस्तुत की गई है। यह पाया गया कि शिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाता (62.7 प्रतिशत) पुरुषों की तुलना में कम वेतन के बारे में संतुष्ट हैं, और शेष उत्तरदाता (37.3 प्रतिशत) कम वेतन के बारे में संतुष्ट नहीं हैं। अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र के उत्तरदाताओं के अनुसार, 65.3 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कम वेतन के बारे में संतुष्ट हैं, और केवल 34.7 प्रतिशत संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षित आदिवासी महिला और अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र की आधी से अधिक महिला उत्तरदाता पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए कम वेतन के बारे में संतुष्ट हैं और उनमें से बाकी संतुष्ट नहीं हैं।

तालिका 5: पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलने के कारण

कारण	शिक्षित आदिवासी महिला	अशिक्षित आदिवासी महिला	कुल
कम उत्पादक	65 (36.1)	39 (30.5)	104 (33.8)
कम गुणात्मक	47 (26.1)	41 (32.0)	88 (28.6)
धीमी गति से काम	11 (6.1)	11 (8.6)	22 (7.1)
यह कस्टम है	35 (19.4)	22 (17.2)	57 (18.5)
महिलाओं के कारण	17 (9.4)	9 (7.0)	26 (8.4)
कोई और	5 (2.7)	6 (4.7)	11 (3.6)
कुल	180 (100.0)	128 (100.0)	308 (100.0)

स्रोत: नमूना डेटा के आधार पर अन्वेषक की गणना

तालिका 5 में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को मिलने वाले कम वेतन के कारणों को दर्शाया गया है। यह देखा गया है कि कुल शिक्षित आदिवासी महिला उत्तरदाताओं में से अधिकांश उत्तरदाताओं 36.1 प्रतिशत की राय है कि महिलाओं की उत्पादकता कम है, और 26.1 प्रतिशत ने महसूस किया कि महिलाओं की उत्पादकता कम है। कुल अशिक्षित आदिवासी महिला उत्तरदाताओं में से, जिसमें उत्तरदाताओं के प्रमुख समूह 32.0 ने कहा कि महिलाओं की उत्पादकता कम है, और 30.5 प्रतिशत ने महसूस किया कि महिलाओं की उत्पादकता कम है। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उत्तरदाताओं के बहुमत समूह की राय है कि शिक्षित आदिवासी महिलाओं में उत्पादकता कम है, जबकि अशिक्षित आदिवासी महिला उत्तरदाताओं की राय में महिलाओं का काम कम गुणात्मक है।

तालिका 6: परिवार के सदस्यों द्वारा खर्च किया गया धन

पैसा खर्चना	शिक्षित आदिवासी महिला	अशिक्षित आदिवासी महिला	कुल
पति	186 (64.8)	124 (63.3)	310 (64.2)
प्रतिवादी	74 (25.8)	62 (31.6)	136 (28.2)
अन्य परिवार के सदस्य	27 (9.4)	10 (5.1)	37 (7.7)
कुल	287 (100.0)	196 (100.0)	483 (100.0)

स्रोत: नमूना डेटा के आधार पर अन्वेषक की गणना

तालिका 6 उन शिक्षित आदिवासी महिला और अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र उत्तरदाताओं को दर्शाती है जिनका पैसा परिवार के सदस्यों द्वारा खर्च किया जाता है। कुल शिक्षित आदिवासी महिला उत्तरदाताओं में से, जिसमें उत्तरदाताओं का एक प्रमुख समूह 64.8 प्रतिशत है, उनके पति द्वारा पैसा खर्च किया जाता है, और 25.8 प्रतिशत स्वयं खर्च कर रही हैं, शेष उत्तरदाता 9.4 प्रतिशत अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरी ओर कुल अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र उत्तरदाताओं में उत्तरदाताओं का एक प्रमुख समूह 63.3 प्रतिशत है, उनके पति द्वारा पैसा खर्च किया जाता है, और 31.6 प्रतिशत स्वयं खर्च कर रही हैं, शेष उत्तरदाता 5.1 प्रतिशत अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पैसा खर्च कर रहे हैं। इसलिए उपरोक्त विश्लेषण, शिक्षित आदिवासी महिला और अशिक्षित आदिवासी महिला उत्तरदाताओं के बहुसंख्यक समूह को इंगित करता है कि वे परिवार में अपने पति के माध्यम से पैसा खर्च कर रही हैं,

तालिका 7: निवेश का निर्णय लेने से पहले महिलाएं परिवार के सदस्यों से सलाह लें

बयान	शिक्षित आदिवासी महिला	अशिक्षित आदिवासी महिला	कुल
हमेशा	144 (50.1)	93 (47.4)	237 (49.1)
कभी-कभी	99 (34.5)	76 (38.8)	175 (36.2)
कभी नहीं	44 (15.3)	27 (13.8)	71 (14.7)
कुल	287 (100.0)	196 (100.0)	483 (100.0)

स्रोत: नमूना डेटा के आधार पर अन्वेषक की गणना

निवेश का निर्णय लेने से पहले महिलाओं द्वारा अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के बारे में उत्तरदाताओं की राय ऊपर दी गई तालिका 7 में प्रस्तुत की गई है। शिक्षित आदिवासी महिला और अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र के उत्तरदाता किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले परिवार के सदस्यों से परामर्श कर रहे हैं। शिक्षित आदिवासी महिला उत्तरदाताओं में से 50.1 प्रतिशत हमेशा परिवार के सदस्यों से परामर्श करते हैं, 34.5 प्रतिशत कभी-कभी परिवार के सदस्यों से परामर्श करते हैं, और शेष 15.3 प्रतिशत उत्तरदाता कभी भी परिवार के सदस्यों से परामर्श नहीं करते हैं। जबकि अशिक्षित आदिवासी महिला से 47.4 प्रतिशत हमेशा परिवार के सदस्यों से परामर्श करती हैं, 38.8 प्रतिशत कभी-कभी परिवार के सदस्यों से परामर्श करती हैं, और शेष 13.8 प्रतिशत उत्तरदाता कभी भी परिवार के सदस्यों से परामर्श नहीं करते हैं। इसलिए, हम कह सकते हैं कि शिक्षित आदिवासी महिला और अशिक्षित आदिवासी महिला क्षेत्र के आधे से अधिक उत्तरदाता किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले हमेशा परिवार के सदस्यों से परामर्श करते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश और हरियाणा में विशेष रूप से विचार करते हुए पुरुष प्रधान समाज के बीच महिलाओं के स्थान का पता लगाने का एक प्रयास है। यह अध्ययन दो उद्देश्यों पर केंद्रित है: पहला उद्देश्य मध्य प्रदेश में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाना है महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति का मतलब है कि एक महिला अपने जीवन में कितने निर्णय ले सकती है और वह निर्णय सही होना चाहिए। अगर एक महिला बेहतर निर्णय लेने वाली है, तो वह कुछ भी हासिल कर सकती है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है जो पहले उद्देश्य को पूरा करता है। परिणामस्वरूप, समग्र अध्ययन से यह देखा गया है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति निम्न है, जिससे समाज में उनकी भूमिका और मूल्य में गिरावट आती है।

संदर्भ

1. अबू तैय्यब एम.एम. भारत में जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ प्योर एप्लाइड मैनेजमेंट साइंसेज। खंड 3, संख्या: 2017, 1।
2. आशीष महापात्रा, "समकालीन ओडिशा के जनजातीय समुदायों में महिलाओं का आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण", अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान जर्नल, खंड 3, संख्या 5।, 2017.
3. मंजूनाथ, गंगाधर. "जेनुकुरुबा आदिवासी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति: चामराजनगर जिले, कर्नाटक का एक केस स्टडी", मानव विज्ञान विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक, भारत प्रकाशित 22/2017, लेख: गैविन प्रकाशित, 5911 डाक रिजवे सूची।, 2017.
4. मनोज एम. गामित, पंकज एस. सुवेरा. "आदिवासी और गैर-आदिवासी कॉलेज छात्रों के बीच सामाजिक-आर्थिक स्थिति का एक अध्ययन", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, खंड 4, अंक 3, संख्या 103।, 2017.
5. संपा दास. "बीरभूम के पाथरघाटा गांव में शिक्षा के माध्यम से संथाल महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण", मानव विज्ञान विभाग, पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय IJEDR/ खंड 5।, 2017.

6. बार्बर, एस., नेपी, एस. संकट में समाजशास्त्र: कोविड-19 और एओटेरोआ न्यूज़ीलैंड में ज्ञान उत्पादन की औपनिवेशिक राजनीति। जर्नल ऑफ़ सोशियोलॉजी, 1-11। कैमरून, ईसी, हेमिंग्वे, एसएल, रे, जेएम, कनिंघम, एफजे, और जैक्विन, केएम (2021) / कोविड-19 और महिलाएँ।, 2020.
7. बैरेंको, आर., और वेंचुरा, एफ. कोविड-19 और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों में संक्रमण: एक उभरती समस्या। मेडिको-लीगल जर्नल, 2020, 1-2।
8. ज़का ए, शामलू एस ई, फियोरेंटे पी, तफ़ुरी ए. कोविड-19 महामारी एक निर्णायक क्षण के रूप में: फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ़ के लिए व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य देखभाल का आह्वान। जर्नल ऑफ़ हेल्थ साइकोलॉजी. 2020;25(7):883-887।
9. कॉनेल आर. कोविड-19/समाजशास्त्र. जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, 2020, 1-7.
10. मोंडल ए, मेटे जे. भारत के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा" यूनिवर्सिटी न्यूज़. 2012;50(20):12-18.
11. डॉ. पटगांवकर एम. एस. महिला उद्यमियों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल (महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले का एक केस स्टडी)" जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट थॉट III-3 (ISSN- 0975-623X -प्रिंट) (0976-478- ऑनलाइन), 2012.
12. रेड्डी एम, रेड्डी पी. एम. "एसएचजी को माइक्रो फाइनेंस-मुद्दे और चुनौतियां" 'बैंकिंग और वित्त' खंड XXV, 2, आईएसएसएन-0971-4498, 2012, 9-17।
13. डॉ. त्रिवेदी सविता, डॉ. भारतीशा राव. "भारत में माइक्रो-फाइनेंस के वर्तमान संकट पर एक अध्ययन" 'बैंकिंग और वित्त' खंड XXV, संख्या 3, आईएसएसएन- 0971-4498, 2012, 5-8।
14. डॉ. सुंदरम ए. भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह का प्रभाव आई ओ एस आर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, आईएसएसएन: 2279-0837, आईएसबीएन: 2279-0845। खंड 5, अंक 1 (नवंबर - दिसंबर 2012), 2012, 20-27।
15. दास संजय के. भूमिगत हकीकतस्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम: एक अनुभवजन्य विश्लेषण" एक त्रैमासिक डबल-ब्लाइंड पीयर रिव्यूड रेफरीड ओपन एक्सेस इंटरनेशनल, ई-जर्नल - इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज। IJRSS (http://www.ijmra.us) खंड 2, अंक 2 ISSN: 2249-2496।, 2012.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.